चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

अन्ना हजारे से चूक हो गई

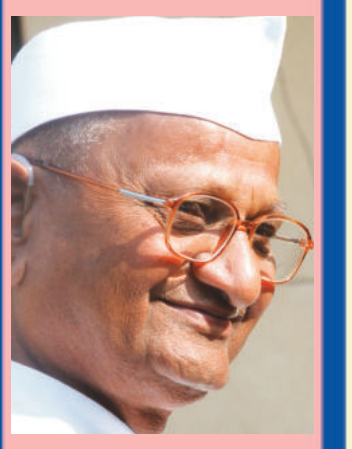

पेज-3

उत्तर प्रदेश चुनाव होगा पहला निशाना

पेज-4

बदलाव की बयार और वाममोर्चा

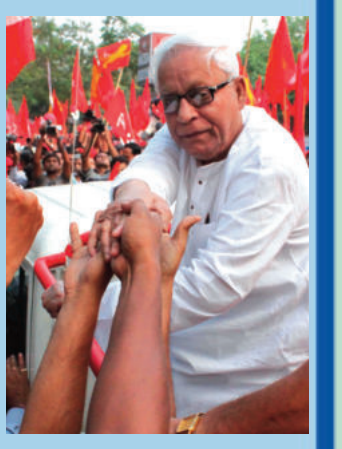

पेज-5

साई की महिमा

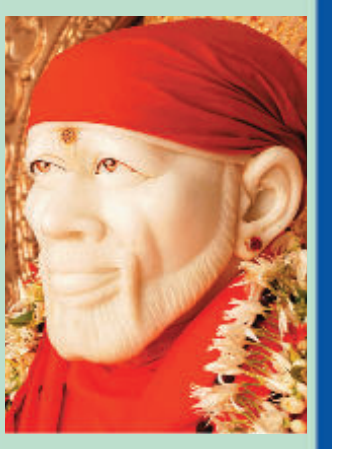

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 02 मई–08 मई 2011 | मूल्य 5 रुपये

महाराष्ट्र सरकार का कारनामा

अब प्यासे मरेंगे अमरावती के किसान

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2003 में विदर्भ में यह ऐलान किया था कि पानी की कमी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं. महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2007 में इंडिया बुल्स को अमरावती में सोफिया पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी. किसानों की आत्महत्या विदर्भ की सबसे बड़ी समस्या है. इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने 87 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सोफिया पावर प्रोजेक्ट को दिए जाने का फ़ैसला किया है. इस पानी पर किसानों का हक़ है. पहले सरकार, फिर स्थानीय नेताओं ने इन किसानों को धोखा दिया. किसानों की आख़िरी उम्मीद सिर्फ़ अदालत है. 6 जून को मुंबई हाईकोर्ट इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई करेगा. सवाल यह है कि इंडिया बुल्स की ऐसी क्या विशेषता है कि पानी की कमी से मर रहे किसानों की जगह सरकार सोफिया पावर प्लांट के साथ खड़ी नज़र आ रही है.

प्रवीण महाजन

नागपुर से 150 किलोमीटर दूर अमरावती ज़िले का माजरी गांव बंजर है. राजस्थान के खेतों में यहां से ज़्यादा हरियाली है. गांव वाले बताते हैं कि यहां की खेती भगवान भरोसे है. वैसे अमरावती ज़िले के इस इलाक़े में अपर वर्धा डैम का पानी पहुंचता है, लेकिन माजरी जैसे कई गांव हैं, जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता. सरकार ने कुछ साल पहले ऐसे गांवों को नहर से जोड़ने की योजना बनाई थी. अपर ब्रिज की तरह नहर बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन चार साल बीत गए, काम शुरू नहीं हुआ है. यहां के किसान खेती छोड़कर शहरों में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं.

अमरावती के किसानों का दूसरा चेहरा माजरी से क़रीब दस किलोमीटर दूर जाफरापुर गांव में देखने को मिलता है. यहां के खेतों में हरियाली है, लेकिन किसानों के चेहरे पर ख़ौफ़ है. इस गांव के किसान पक्के मकानों में रहते हैं, कुछ के पास गाड़ियां हैं. इस गांव के किसान ग़रीब नहीं हैं, लेकिन भविष्य को लेकर चिंतित हैं. पहले यहां के किसान खेती के लिए मानसून पर निर्भर थे. सरकार ने अपर वर्धा डैम बनाकर यहां के किसानों की ज़िंदगी बदल दी. अब हालत यह है कि डैम से सही मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है. यही वजह है कि यहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं. पिछले साल गेहूं की फ़सल ख़राब हो गई. इलाक़े के किसान कहते हैं कि गेहूं को 8 बार पानी की ज़रूरत पड़ती है. पिछले साल बारिश भी पूरी हुई थी, इसके बावजूद डैम से सिर्फ़ 6 बार ही पानी छोड़ा गया. आख़िरी दो बार के पानी के लिए किसान इंतज़ार करते रह गए, लेकिन पानी का एक कतरा भी डैम से नहीं छोड़ा गया. गांव वाले बताते हैं कि 2009 में एक बार भी पानी नहीं छोड़ा गया. तो सवाल यह है कि डैम का पानी आख़िर जाता कहां है? इसे किसके लिए बचाया जाता है? सरकार ने इस इलाक़े में सोफिया विद्युत परियोजना शुरू की है. डैम का पानी वहां भेजा जा रहा है. समझने वाली बात यह है कि अपर वर्धा डैम का निर्माण सिर्फ़ सिंचाई के लिए किया गया था. इसके पानी पर किसानों का अधिकार है. समझ में नहीं आता है कि आख़िर सरकार किसानों की दुश्मन क्यों बन गई है? सच्चाई यह है कि विदर्भ में नेताओं, अधिकारियों एवं पूंजीपतियों ने मिलजुल कर ऐसा तांडव मचाया है कि अमरावती के लाखों किसानों की ज़िंदगी अधर में लटक गई है.

पानी की कमी का असर इन किसानों पर होना शुरू हो गया है. गेहूं, चना और सोया की खेती की जगह वे कपास की खेती करने को मजबूर हैं. सोफिया को पानी दिए जाने के ख़िलाफ़ गांव वाले आंदोलन कर रहे हैं. वे कहते हैं कि अपनी जान दे देंगे, लेकिन पानी के लिए लड़ेंगे. इस इलाक़े में इस आंदोलन से जुड़े संजय देशमुख बताते हैं कि सरकार सोफिया परियोजना पर इतनी मेहरबान है कि सारे नियम-क़ानूनों को ताख पर रख दिया गया है. सोफिया परियोजना के पीछे किन-किन उद्योगपतियों और नेताओं का हाथ है, इसे लेकर कई अफवाहें हैं. दिल्ली और मुंबई के कई बड़े-बड़े लोगों के नाम इसमें लिए जा रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी है. मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है, लेकिन अमरवती में आएदिन कुछ न कुछ ज़रूर होता रहता है. हाल में ही गांव के लोगों ने सोफिया जा रहे बालू से लदे ट्रकों को रोका. सोफिया में इस्तेमाल हो रही बालू ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से लाई जा रही है. रात के अंधेरे में ट्रकों की आवाजाही गांव वालों ने रोकी तो ट्रकों ने अब रास्ता बदल दिया है. आज की स्थिति यह है कि सोफिया कंपनी और इलाक़ाई लोगों के बीच आर-पार की लड़ाई है. क़ानून की धज्जियां उड़ाती इस कंपनी को गांव वालों का आंदोलन महंगा पड़ सकता है. जाफ़राबाद की संगीता दशरथ राव कहती हैं कि सोफिया में पानी गया तो कटोरा लेकर भीख मांगकर खाना पड़ेगा, इसलिए मरते दम तक लड़ूंगी.

सरकार की यह आदत सी बन गई है कि वह ग़रीब किसानों का हक़ छीनकर किसी निजी कंपनी या किसी औद्योगिक समूह को लाभ पहुंचाती है. महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में बन रही ताप विद्युत परियोजना सोफिया पावर का मामला भी ऐसा ही है. सोफिया ताप विद्युत परियोजना के पीछे इंडिया बुल्स नामक कंपनी है. इस परियोजना को लेकर तो हो-हल्ला हो ही रहा है, लेकिन विरोध का स्वर धीमा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जो मीडिया से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक, हर विरोधी और समर्थक की पूरी जानकारी अपने पास रखता है. सवाल यह है कि विदर्भ में वैसे ही पानी की कमी है, फिर ऐसे में उस परियोजना को अनुमति कैसे दी जा सकती है, जिसमें भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है. वैसे सरकार ने बड़ी चालाकी से यह काम किया है. सरकार ने इस कंपनी को महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन की ज़मीन दी है. नियम और क़ानून की नज़र से तो यह परियोजना वैध है, लेकिन किसानों को जब पानी नहीं मिलता है तो इसका असर सीधे पेट पर पड़ता है. यही वजह है कि जनता ने सरकार पर हमला बोल दिया है. स्थानीय नेताओं ने अपनी भौंहें चौड़ी कर दीं. विधायक बच्चू कडू ने तो इसके विरोध में विधानसभा में अपनी कमीज तक उतार दी. राज्य विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौक़ा था, जब किसी विधायक ने सदन के भीतर अपनी कमीज निकाली हो. रही-सही कसर सोफिया हटाओ संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके पूरी कर दी.

एक तरफ़ गांव वालों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ़ इस परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है. सरकार की दलील है कि इस परियोजना से राज्य को बिजली मिलेगी. अपर वर्धा सिंचाई परियोजना में 24.735 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी एमआईडीसी के लिए सुरक्षित रखा गया है. लेकिन सोफिया हटाओ संघर्ष समिति को एतराज इस बात पर है कि इस पानी के संपूर्ण औद्योगिक कोटे का सिर्फ़ सोफिया के लिए इस्तेमाल करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसके बाद 2347 हेक्टेयर में फैले नंदगांव पेठ औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी बचेगा ही नहीं. हालात यह हैं कि अमरावती ज़िले में अभी भी 2,43,440 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है. इस परियोजना को अगर पानी दिया जाता है तो 23,219 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि असिंचित हो जाएगी. सरकारी आंकड़े भी यही कहते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग का कहना है कि पानी की कमी उक्त क्षेत्रफल में चरणबद्ध रूप से होगी. यानी पूरी तरह ज़मीनें असिंचित नहीं रहेंगी. फ़िलहाल अपर वर्धा परियोजना से 75,080 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा है.

विदर्भ में ताप विद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रही समूह आंदोलन समिति के विवेकानंद माथने का कहना है कि विदर्भ अभी भी अपनी खपत से अधिक विद्युत का उत्पादन करता है,

(शेष पृष्ठ 2 पर)

क्या है इंडिया बुल्स

इंडिया बुल्स देश की सबसे चर्चित कंपनी मानी जाती है. इंडिया बुल्स समूह के मुख्य प्रवर्तक समीर गहलौत, राजीव रतन और सौरभ मित्तल आईआईटी, दिल्ली के ग्रेजुएट हैं. यह कंपनी 1999 के मध्य में स्थापित की गई और शुरुआती दौर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता लेने के बाद इसने शेयर की ब्रोकरेज सेवा प्रदान करनी शुरू की. कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की इस कंपनी में रुचि बताई जाती है. बताते हैं कि इंडिया बुल्स समूह को सरकारी महकमे से बड़ी-बड़ी मंजूरियां आसानी से मिल जाती हैं. यह समूह रीयल इस्टेट, बिजली एवं रिटेल से लेकर विभिन्न वित्तीय सेवाओं में सक्रिय है. इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रस्तावित जीवन बीमा कंपनी में रिजर्व बैंक की तरफ़ से 74 फ़ीसदी निवेश की इजाज़त मिलने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है.

इंडिया बुल्स और विवाद

इंडिया बुल्स का नाम भले ही एक सफल कंपनी के रूप में लिया जाता है, लेकिन विवादों से भी इसका पुराना नाता रहा है. ग्राहकों को इस कंपनी के बारे में एक आम शिकायत हमेशा रहती है. मसलन, अधिक वसूली, भुगतान में देरी और निवेशकर्ताओं के एकाउंट से ग़ैर क़ानूनी ढंग से पैसा निकाल लेना. ख़ुद इंडिया बुल्स के कर्मचारी अपनी ही कंपनी पर प्रोविडेंट फंड को लेकर आरोप लगा चुके हैं. 2007 में फ्यूचर एंड ऑप्शन (एफ एंड ओ) मार्केट से संबंधित मामले में इंडिया बुल्स द्वारा बेईमानी एवं ग़लत रास्ता अपनाने के आरोप की जांच करने के बाद सेबी ने इस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कंपनी के कुछ आला अधिकारियों के ख़िलाफ़ एक गंभीर आरोप पर चल रही जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. इन अधिकारियों पर ग़ैर क़ानूनी रूप से अपने ग्राहकों के एकाउंट से पैसा निकालने के आरोप थे.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने उन बाबुओं की नकेल कसने में लगा हुआ है, जिन्होंने बार-बार कहने के बाद भी अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, जबकि ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाबुओं पर सख्त डीओपीटी

पिछले कुछ महीनों से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने उन बाबुओं की नकेल कसने में लगा हुआ है, जिन्होंने बार-बार कहने के बाद भी अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, जबकि ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है. इसलिए अब इस विभाग ने ऐसे बाबुओं को रास्ते पर लाने के लिए एक तरीक़ा निकाला है. मसलन, पदोन्नति के लिए उन्हें अपनी संपत्ति की जानकारी विभाग को देनी ही पड़ेगी. नतीजतन, इस आदेश का बाबुओं पर काफी असर पड़ा और ख़ासकर आंध्र प्रदेश के आईएएस अधिकारियों पर, जहां 282 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी विभाग के सुपुर्द कर दी है. हालांकि अभी भी 80 अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया है. राज्य के मुख्य सचिव एस वी प्रसाद ने बाबुओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनकी पदोन्नति रोकी जा सकती है.

डीजीसीए की बढ़ती मुश्किलें

फ़र्ज़ी पायलटों के मामले सामने आने के बाद अंदरूनी सूत्र इस सबके लिए कुछ अन्य वजहों का हवाला दे रहे हैं. यह बात तो बिल्कुल ही साफ है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) स्टाफ की गंभीर कमी से जूझ रहा है और अस्थायी सलाहकारों के भरोसे अपना काम चला रहा है. इस संस्था के पास अभी 140 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं. यह संख्या इस घोटाले की जांच की वजह से और घट सकती है. सूत्रों के अनुसार, नागरिक उड्डयन सचिव नसीम जैदी और डीजीसीए प्रमुख भारत भूषण भले ही इस क्षेत्र के लिए नए नहीं हैं, फिर भी उन्हें अपने पदों पर आए कुछ ही समय हुआ है. फ़िलहाल वे इस समस्या से जूझने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी समस्या दूर होगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि इस घोटाले (फर्जी पायलट) की वजह से और कितना नुक़सान उठाना पड़ सकता है.

एनएचएआई में हलचल

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दिक्कतें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं. पहले से ही नए चेयरमैन की नियुक्ति का मामला लंबित है और अब सरकार ने कहा है कि किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि किसी टेक्नोक्रेट को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा. ऐसा करने से नियुक्ति में तेजी आएगी, ऐसा मानना मुश्किल है. बहरहाल, इस संगठन के बाबुओं का असली सिरदर्द एक वरिष्ठ प्रबंधक और तत्कालीन सतर्कता प्रमुख के बीच जारी छींटाकशी है. वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) राजेश गुप्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत करते हुए कहा है कि इस संगठन के तत्कालीन सतर्कता प्रमुख आर मुकुंदन ने घूस मांगी और इसकी जांच होनी चाहिए. दूसरी ओर मुकुंदन के अनुसार, गुप्ता ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना दी. उन्होंने भी केंद्रीय सतर्कता आयोग से इसकी शिकायत की है. ऐसे माहौल में नए चेयरमैन की नियुक्ति जल्द से जल्द हो जानी चाहिए.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

अतुल बने मुख्य सलाहकार

उत्तर प्रदेश कैडर और 1974 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल चतुर्वेदी को कैबिनेट सचिवालय में मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है. उन्हें तीन महीने के लिए इस पद पर तैनात किया गया है. ग़ौरतलब है कि चतुर्वेदी इस्पात मंत्रालय में सचिव थे और रिटायर हो चुके थे. अब उन्हें मुख्य सलाहकार बनाया गया है, जो नवसृजित पद है.

शुभ्रा बन सकती हैं जेएस

वर्ष 1989 बैच और राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह का नाम खाद्य एवं जन वितरण विभाग में संयुक्त सचिव पद के लिए चर्चा में है. सूत्रों का कहना है कि इस बार उन्हें यह पद मिल सकता है. कुछ समय पहले भी वह इस पद पर तैनात होते-होते रह गई थीं.

जेएस कौन बनेगा

वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात राजीव खेर को इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया है. अब रिक्त पद को भरने के लिए एक पैनल गठित किया गया है. इस पद के लिए 1983 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार दादू और 1986 बैच के आईएएस अधिकारी अंशु प्रकाश के नाम चर्चा में हैं.

सेवा विस्तार

मध्य प्रदेश कैडर और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एस के पांडेय अभी एसपीजी में आईजी के पद पर तैनात हैं. उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है.

नारायण बनेंगे एडीजी

सुधीर रंगप्पा यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नवसृजित सहायक महानिदेशक पद पर तैनात किए जा सकते हैं. नारायण 1988 बैच के आईडीएएस अधिकारी हैं.

अब प्यासे मरेंगे अमरावती के किसान

सोफिया परियोजना से कई सवाल उठ रहे हैं. इस परियोजना का विदर्भ में क्या काम, जबकि विदर्भ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पहले से बना रहा है? विदर्भ में पानी की कमी है, फिर भी पानी पर चलने वाली बिजली परियोजना को वहां लगाने का क्या मक़सद है?

पृष्ठ एक का शेष

सोफिया के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा. इसके बाद असंतोष और तेजी से बढ़ा, क्योंकि इसमें तथ्य छुपाए गए थे. एक विधायक (जो सोफिया के पक्ष में हैं) की मानें तो 2640 मेगावाट की निर्माणाधीन परियोजना के प्रथम चरण में 87.60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है. जबकि अमरावती के सीवेज से अधिकतम 2.4 करोड़ लीटर पानी ही निकलता है, इसलिए सोफिया को काउडन्यापुर बांध से पानी की आपूर्ति होगी. यहां ग़ौर करने वाली बात यह है कि बांध अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि सोफिया प्रकल्प 6 माह में शुरू हो जाएगा. अब सीवेज का पानी मिले या न मिले, मगर यह साफ है कि अब गंदे पानी पर भी दावेदारी शुरू हो गई है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है. वैसे अमरावती में गंदे पानी को रिसाइकिल करने की परियोजना का मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. नगरपालिका ने इस परियोजना के लिए ज़मीन भी अधिग्रहीत कर ली है. शहर में बहने वाले अंबा नाले का उपयोग गंदे पानी की निकासी के लिए किया जाता है. इसके पानी से 400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है. मजे की बात यह है कि नाले से बहकर जो पानी पेडी नदी में मिलता है, उस पर भी बांध बनाने की परियोजना प्रस्तावित है, जो 500 करोड़ रुपये की है. पेडी नदी में अंबा नाले के पानी की हिस्सेदारी 40 फ़ीसदी है. फिर भी इस परियोजना को सही ठहराया जा रहा है.

अमरावती में अपर वर्धा डैम

सोफिया पॉवर प्लांट में तेज़ी से होता निर्माण कार्य

सोफिया का विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि अमरावती ज़िले में पेयजल व्यवस्था, संपूर्ण महाराष्ट्र की सिंचाई, सरकारी नियमानुसार उद्योगों के लिए 10 प्रतिशत जल और कृषि आधारित उद्योगों को आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमरावती ज़िले में तहसीलवार पानी का ऑडिट किया जाना चाहिए. वर्तमान में अमरावती में अपर वर्धा, शहानूर, चंद्रभागा, चारगढ़, पूर्णा और अन्य छोटे-मोटे तालाबों से 112.75 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जा रहा है, फिर भी गांवों में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है. ज़िले के 472 गांवों में पानी की किल्लत है. इनमें से 25 गांवों में तो ग्रीष्मकाल में टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाना पड़ता है. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक बनाए गए जल प्रकल्पों से जून 2009 तक पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 230.22 प्रतिशत, सांगली में 107.35 प्रतिशत, पुणे में 76.99 प्रतिशत, सतारा में 82.57 प्रतिशत और सोलापुर में 66.88 प्रतिशत सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है. जबकि अमरावती संभाग के किसी भी ज़िले में यह क्षमता 25 फ़ीसदी का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है. यवतमाल ज़िले में ज़रूर 35.32 फ़ीसदी सिंचाई क्षमता विकसित करने का सरकारी दावा है. महाराष्ट्र की अनुमानित औसत सिंचाई क्षमता 56.14 फ़ीसदी है. अमरावती ज़िले का सिंचाई बैकलाग वैसे भी पूरे राज्य में सबसे अधिक है. यहां जून 2009 तक की जानकारी के अनुसार, 2,43,440 हेक्टेयर में अभी भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है. इसके बावजूद अमरावती में सिंचाई की जगह पानी उद्योगों को देना सवालिया निशान ही खड़ा करता है.

सोफिया बिजली परियोजना से किसानों को पानी की किल्लत तो हो ही रही है, इसकी मार इलाक़े के पर्यावरण पर भी ज़बरदस्त पड़ने वाली है. छत्तीसगढ़ के कोरबा, अमरावती के नज़दीक चंद्रपुर में ताप विद्युत परियोजनाओं का अनुभव अच्छा नहीं है. यहां चिमनियों से उड़ती राख पूरे क्षेत्र को ही अपने आगोश में ले लेती है. यही कारण है कि कोरबा, चंद्रपुर जैसे शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं. निसर्ग संरक्षण संस्था के अध्यक्ष निशिकांत काले की सलाह है कि इंडिया बुल्स को यहां पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए. ताप विद्युत परियोजना से अमरावती सहित तिवसा, मोर्शी तहसीलों की फ़सलों पर भी विपरीत असर पड़ेगा. सरकार का कहना है कि राज्य में बिजली की कमी को देखते हुए सोफिया ताप विद्युत प्रकल्प रद्द नहीं किया जा सकता. साथ ही इसका निर्माण कार्य काफी हो चुका है. सरकार ने इस परियोजना के कारण सिंचाई से प्रभावित होने वाली 23,219 हेक्टेयर ज़मीन के संबंध में व्यापक अध्ययन करने के भी आदेश दिए हैं, जिससे इस ज़मीन पर सिंचाई क्षमता में कमी न आए. गत वर्ष 17 जून को जल संसाधन मंत्री, उद्योग मंत्री, अमरावती ज़िले के पालक मंत्री, ज़िले के सभी विधायकों, सांसद, सोफिया समर्थकों और विरोधियों की बैठक बुलाई गई थी. इसमें 10 विधायक एवं एक सांसद उपस्थित थे. बैठक में सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए, उनमें यह भी शामिल था कि सोफिया प्रकल्प पूरा होने के बाद राज्य की नीति के अनुसार अमरावती ज़िले को लोडशेडिंग से मुक्त कर दिया जाएगा. कभी विकास के नाम पर तो कभी बिजली के नाम पर, क्या हर बार ग़रीब किसानों का हक़ ही छीना जाएगा?

अब सवाल उठ रहा है कि उद्योगों और बिजली परियोजनाओं को पानी देने का अधिकार किसे है? सिर्फ़ अमरावती का ही मामला नहीं है, यह प्रश्न पूरे देश के लिए है. महाराष्ट्र के लिए यह ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है. वैसे भी गर्मी के दिनों में पूरे राज्य में जल संकट गहरा जाता है. औरंगाबाद में साल भर दो दिनों में एक बार पानी की आपूर्ति की जाती है. पानी के इस्तेमाल में सुधार के लिए सरकार ने 2005 में बाकायदा क़ानून बनाकर महाराष्ट्र जल संपदा नियमन प्राधिकरण की स्थापना की. अलग-अलग उपयोग के लिए पानी की दरें निर्धारित करने का अधिकार इस प्राधिकरण को दिया गया. हालांकि सरकार ने पानी के उपयोग पर अपनी बादशाहत क़ायम रखी. इस कारण पानी पर जन भागीदारी बढ़ाने के मिशन पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है. प्राधिकरण की स्थापना का मूल उद्देश्य ही यह था कि पानी का समान वितरण हो, पानी की बर्बादी रुके, इसे प्रदूषण मुक्त रखा जाए. पानी देने का अधिकार इस प्राधिकरण के पास ज़रूर है, परंतु निर्णय शासन की उच्चाधिकार समिति करती है. इसी उच्चाधिकार समिति ने 21 फरवरी, 2008 को सोफिया पावर कंपनी को 549.98 करोड़ रुपये के एवज में 87.60 मिलियन क्यूबिक मीटर (दस लाख घन मीटर) पानी देने और 29 अप्रैल, 2008 को अमरावती थर्मल पावर कंपनी को 95.20 करोड़ रुपये के एवज में 35.92 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बेचने का निर्णय ले लिया.

सोफिया परियोजना से कई सवाल उठ रहे हैं. इस परियोजना का विदर्भ में क्या काम, जबकि विदर्भ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पहले से बना रहा है? विदर्भ में पानी की कमी है, फिर भी पानी पर चलने वाली बिजली परियोजना को वहां लगाने का क्या मक़सद है? सोफिया परियोजना में किन-किन लोगों का हाथ है? इंडिया बुल्स कंपनी में किन-किन लोगों का पैसा लगा है? सरकार पर इस परियोजना को पास करने के लिए कहां-कहां से दबाव पड़ा? जो नेता कल तक इसके विरोध में थे, आज उनके सोफिया के पक्ष में खड़े होने के लिए क्या और किससे डील हुई? इस परियोजना को लेकर मीडिया भी शक के घेरे से बाहर नहीं है. कल तक सच बताने वाला मीडिया आज ग़रीब किसानों के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा है? इन सवालों के जवाब सरकार और जांच एजेंसियों को देने चाहिए. अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो जनता का विश्वास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों, नेताओं एवं अधिकारियों ने प्रजातंत्र को विकृत कर दिया है. बिजली बनानी हो तो किसानों-आदिवासियों की कुर्बानी ली जाती है. सड़क बनानी हो तो किसानों की ज़मीन छीन लो, एसईजेड बनाना हो तो किसानों की ज़मीन हड़प लो, शहरीकरण करना हो, मॉल्स बनाने हों या फिर आवासीय कालोनी बनानी हो तो किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण कर लो. फिर होता यह है कि हर परियोजना भ्रष्टाचार के घेरे में आ जाती है. जिन उद्देश्यों को लेकर परियोजनाएं शुरू होती हैं, वे कभी पूरे नहीं हो पाते हैं. इन परियोजनाओं से अधिकारियों, नेताओं और दलालों की जेबें ज़रूर गरम हो जाती हैं. बेचारा किसान सरकार और विकास के सपने के बीच ऐसा फंस जाता है कि ज़मीन न छोड़े तो विकास विरोधी कहलाता है और ज़मीन छोड़ दे तो भिखारी बन जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 8
दिल्ली, 02 मई-08 मई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

विशेष संवाददाता
सरोज कुमार सिंह (बिहार)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

देश की जनता इंतजार कर रही थी कि कोई व्यक्ति होगा, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगा, पर लगता है कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई इन लोगों ने मिलकर शुरू की, वह टूटने लगी है, बिखरने लगी है.

अन्ना हजारे से चूक हो गई

ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे और उनके साथियों का लक्ष्य जन लोकपाल बिल को लागू कराना नहीं, बल्कि उसका श्रेय लेना है. अगर जन लोकपाल बिल को लागू कराना मक़सद था तो एक ही दांव में जन लोकपाल बिल क़ानून बन जाता और सरकार को संभलने का मौक़ा तक न मिलता. अगर इस कमेटी में अरुण जेटली, सीताराम येचुरी, सुब्रमण्यम स्वामी, फाली एस नरीमन और अरविंद केजरीवाल होते तो ये सरकारी प्रतिनिधियों पर न सिर्फ़ भारी पड़ते, बल्कि इस बिल को संसद में पास होने की गारंटी भी मिल जाती.

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

अन्ना हजारे का आंदोलन दिशाहीनता का शिकार हो गया है. दिशाहीनता कई स्तर पर नज़र आ रही है. दिशाहीनता का मतलब इस बात से है कि अन्ना हजारे और उनके सर्वगुण संपन्न मैनेजरों ने आंदोलन तो शुरू कर दिया, लेकिन वे यह अनुमान ही नहीं लगा पाए कि आने वाले दिनों में कौन–कौन सी चुनौतियां सामने आने वाली हैं. अपने बयानों और व्यवहारों से उन्होंने दोस्तों को भी दुश्मन बना दिया. एक ही झटके में दुश्मनों को एकजुट होने की वजह दे दी. सबसे मजेदार बात यह है कि जिनके ख़िलाफ़ वे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, आज वे भ्रष्टाचार मिटाने वाले दिख रहे हैं और जो देश से भ्रष्टाचार मिटाने निकले थे, वही भ्रष्ट साबित हो रहे हैं. आंदोलन की ख़ासियत यह है कि जन समर्थन से इसने अभूतपूर्व सफलता पाई, लेकिन पहली ही बैठक में सब कुछ गंवा दिया.

देश की जनता इंतजार कर रही थी कि कोई व्यक्ति होगा, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगा, पर लगता है कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई इन लोगों ने मिलकर शुरू की, वह टूटने लगी है, बिखरने लगी है. ज़रा सोचिए, एक तरफ़ प्रणव मुखर्जी, पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली एवं सलमान खुर्शीद और दूसरी तरफ़ शांतिभूषण और प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े एवं अरविंद केजरीवाल. सरकार की तरफ़ से जिन लोगों को इस कमेटी में रखा गया है, वे क़ानून और राजनीति के दिग्गज हैं, अपनी दलीलों से विरोधियों को धराशायी करने में माहिर हैं. और दूसरी तरफ़, क़ानून के दो जानकार शांतिभूषण और प्रशांत भूषण हैं. दोनों आरोपों के घेरे में हैं. शांतिभूषण पर उम्र का असर भी दिखता है. वैसे अंग्रेजी नहीं जानना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमारा देश भी तो अजब है. जन लोकपाल विधेयक का मसौदा भी अंग्रेजी में बना है, बहस अंग्रेजी में होगी, क्योंकि कमेटी के कई लोगों को हिंदी नहीं आती. अब अन्ना हजारे इस बहस में कैसे हिस्सा लेंगे, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती और न ही वह क़ानून के ऐसे जानकार हैं, जो सरकारी सदस्यों को पछाड़ सकें. अरविंद केजरीवाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं. यह अकेले सदस्य हैं, जो मीटिंग के दौरान सरकारी पक्ष से जवाब तलब कर रहे थे. जब आप किसी मीटिंग में निगोसिएशन कर रहे हैं तो सामने वाले से आपके अंदर की शारीरिक और मानसिक शक्ति इक्कीस ही होनी चाहिए, उन्नीस नहीं. यही बात अन्ना हजारे को समझ में नहीं आई. जब पहली मीटिंग के बाद ये लोग बाहर आए तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया कि अंदर क्या हुआ. पहली मीटिंग में लोकपाल की नियुक्ति और मीटिंग की वीडियोग्राफी पर बात हुई. दोनों ही मुद्दों पर सरकारी पक्ष हावी रहा. लोकपाल की नियुक्ति की जिम्मेदारी में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हो गए. ठीक वैसे ही, जैसे चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति में होता है. इसी नियम की तरह पी जे थॉमस की नियुक्ति हुई थी. पी जे थॉमस पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, फिर भी वह इसी नियम के तहत सीवीसी बनने में कामयाब रहे थे. इस मुद्दे पर सरकार कठघरे में आ गई. मीटिंग की वीडियोग्राफी पर भी सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों को सफलता नहीं मिली. इस मीटिंग में ऑडियो रिकार्डिंग पर ही सहमति बन पाई. लोकपाल कानून बनाने की इस लड़ाई में एक आर्मी जनरल का बयान याद आता है, जो उसने 1971 के युद्ध के बारे में दिया था. वह बयान यह था कि हम पाकिस्तान से मैदान में युद्ध तो जीत गए, लेकिन शिमला में टेबल पर हार गए. डर इस बात का है कि यह सच साबित न हो जाए.

अन्ना हजारे से कई ग़लतियां हुई हैं, जिससे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन ही दिशाहीन हो गया. पहला झटका बाबा रामदेव ने दिया, जब उन्होंने बिल ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के लिए किरण बेदी का नाम सुझा दिया. यह पता चल गया कि आंदोलन कर रहे लोगों में एकजुटता नहीं है. इस आंदोलन की कमियां जैसे ही उजागर हुईं, दलालों ने हमले शुरू कर दिए हैं. प्रशांत भूषण और शांति भूषण, जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, उन पर नए–नए आरोप लगे. इस पूरी कहानी के बीच एक कहानी छुप सी गई है और वह कहानी है कि काले धन को लेकर इस देश में जो जनांदोलन या जनाक्रोश शुरू हुआ, वह बाबा रामदेव से शुरू हुआ. फिर अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया. बाबा रामदेव और अन्ना हजारे में दूरियां आ गईं. आंदोलन जैसे ही अलग–थलग हुआ, दलालों ने सच के सिपाहियों पर हमले शुरू कर दिए.

अन्ना हजारे से लोगों की उम्मीद बंधी थी, लेकिन यह समझ लेना भी कि सिर्फ़ आंदोलन में शामिल लोग ही प्रतिनिधित्व करते हैं, सिविल सोसायटी की एक भूल है. जो राजनेता आए, उन्हें वहां से भगा दिया गया. ओम प्रकाश चौटाला, उमा भारती को भगा दिया गया और अनुपम खेर के आने पर सब लोग प्रसन्न हो गए. किसी भी आंदोलन में अगर किसी नेता का समर्थन मिलता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए. यह भी एक भूल थी. आंदोलन ख़त्म होने के बाद जब शांतिभूषण और प्रशांत भूषण पर आरोप लगा तो अन्ना ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी. सोनिया का जवाब भी आ गया. यह भी एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम था. एक और गलती यह हुई कि पूरे आंदोलन पर चार–पांच लोग कब्जा किए हुए बैठे थे. इसका एक उदाहरण बाबा रामदेव भी हैं. बाबा रामदेव कोई आम व्यक्ति नहीं हैं. बाबा रामदेव जंतर मंतर आए तो उन्हें वहां बैठने भी नहीं दिया गया. अन्ना हजारे के आंदोलन को 82 लाख रुपये मिले हैं, जिनमें 37 लाख ख़र्च हुए. ख़बर यह भी आई कि पैसा कांग्रेसी परिवार जिंदल ने दिया. आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर सिर्फ़ अन्ना हजारे ही नहीं भूख हड़ताल कर रहे थे, बल्कि उनके साथ डेढ़ सौ आदमी भी अनशन पर बैठे. इन लोगों ने तीन–तीन दिनों तक भूख हड़ताल की, लेकिन उनका नाम तक नहीं लिया गया. अन्ना हजारे को उनके बीच में बैठना था. कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस द्वारा संचालित था, ताकि बाबा रामदेव का आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए. एक परिवार से दो आदमियों को रखना सबसे बड़ी भूल है.

बाबा रामदेव और अन्ना हजारे में एक समानता यह है कि दोनों बहुत ही सिक्रेटिव हैं. दोनों ही अपने कुछ चंद सलाहकारों की बातों पर चलते हैं. दोनों हर चीज को अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि कोई भी आए, वह उनके अधीन काम करे. बाबा रामदेव की समस्या यह है कि वह गुरुकुल में पढ़े हैं. दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज का बाबा रामदेव पर काफ़ी असर है. दिमाग़ी तौर पर उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काफ़ी असर है. कई बार भाषणों में वह अखंड भारत की पैरवी करते हैं. सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो आंदोलन है, वह ख़त्म हो चुका है. मेरा मानना है कि अभी यह ख़त्म नहीं हुआ है. इसके सूत्रधार न बाबा रामदेव हैं और न अन्ना हजारे. फेल हो जाने दो दोनों को, कोई और लीडर आ जाएगा. कमी थोड़े ना है इस देश में लीडरों की.

ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे और उनके साथियों का लक्ष्य जन लोकपाल बिल को लागू कराना नहीं, बल्कि उसका श्रेय लेना है. अगर जन लोकपाल बिल को लागू कराना मक़सद था तो एक ही दांव में जन लोकपाल बिल क़ानून बन जाता और सरकार को संभलने का मौक़ा तक न मिलता. अन्ना हजारे यह समझ नहीं सके कि इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ने वाले आदमियों की कोई कमी नही है. वह यह भी नहीं समझ सके कि राजनीतिक दलों से लड़ने के लिए राजनीति आनी चाहिए. क़ानून के जानकारों की भी कमी नहीं है और यह कहना कि जन लोकपाल बिल हमने बनाया है और इसे कोई दूसरा समझ नहीं सकता, यह बात भी ग़लत है. अन्ना हजारे को चाहिए था कि आंदोलन की सफलता के बाद वह कमेटी के लिए ऐसे लोगों के नाम आगे करते, जिससे लोकपाल बिल न सिर्फ़ तैयार हो जाता, बल्कि संसद में इसे पारित होने की गारंटी भी मिल जाती. अगर इस कमेटी में अरुण जेटली, सीताराम येचुरी, सुब्रमण्यम स्वामी, फाली एस नरीमन और अरविंद केजरीवाल होते तो ये सरकारी प्रतिनिधियों पर न सिर्फ़ भारी पड़ते, बल्कि इस बिल को संसद में पास होने की गारंटी भी मिल जाती.

manish@chauthiduniya.com

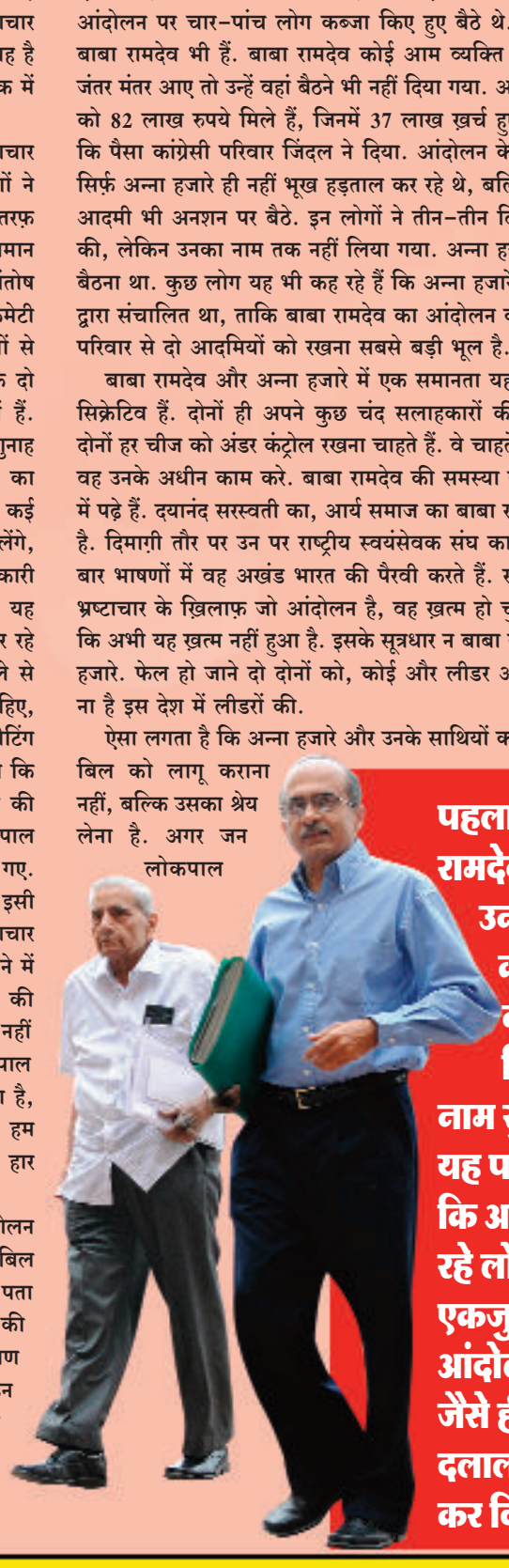

पहला झटका बाबा रामदेव ने दिया, जब उन्होंने बिल ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के लिए किरण बेदी का नाम सुझा दिया. यह पता चल गया कि आंदोलन कर रहे लोगों में एकजुटता नहीं है. इस आंदोलन की कमियां जैसे ही उजागर हुईं, दलालों ने हमले शुरू कर दिए हैं.

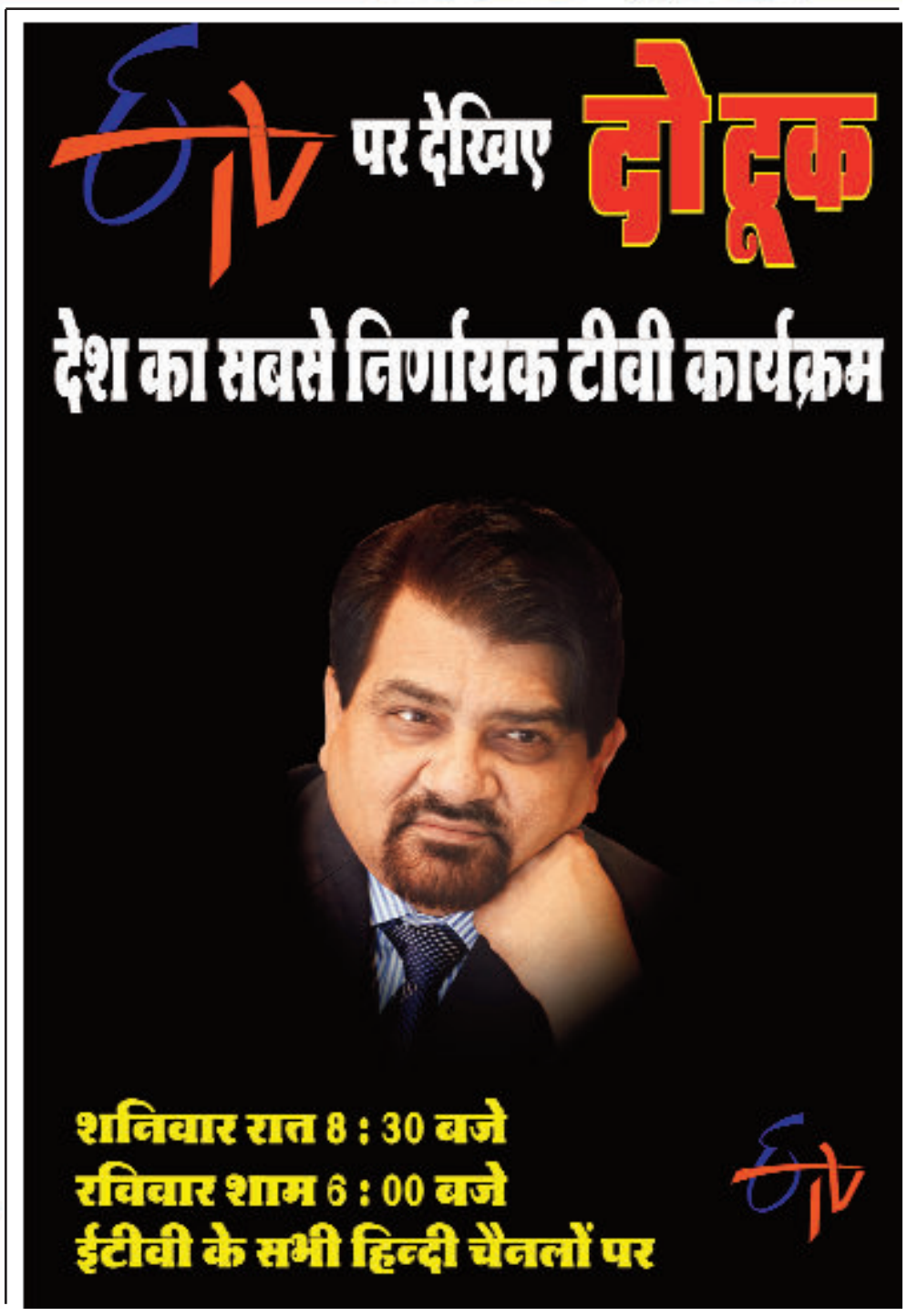

जमात-ए-इस्लामी की स्थापना 26 अगस्त, 1941 को लाहौर में हुई थी. देश के बंटवारे के बाद जमात-ए-इस्लामी भी बंट गई. पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी जमात-ए-इस्लामी है.

जमात-ए-इस्लामी ने नई पार्टी बनाई

उत्तर प्रदेश चुनाव होगा पहला निशाना

फोटो– *सुनील मल्होत्रा*

फ़िरदौस ख़ान

एक नई पार्टी बनी है. इस पार्टी के उद्घाटन समारोह में एक क्रिश्चियन पादरी ने गायत्री मंत्र पढ़ा तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस पार्टी की जड़ में जमात-ए-इस्लामी हिंद है, जिसके बारे में लोग यह मानते हैं कि यह एक कट्टर मुस्लिम संगठन है. यह सच है कि कोई सियासी पार्टी मुसलमानों के विकास के बारे में ईमानदारी से नहीं सोचती, बस नारे ही देती है. भारतीय राजनीति में मौजूदा घोर अवसरवाद के बीच यह मुसलमानों की ज़रूरत बन गई थी कि एक ऐसा राजनीतिक दल हो, जो उनके दर्द को समझे, उनकी चुनौतियों को जाने, मुस्लिम युवाओं के रोज़-गार के लिए लड़े, उनके सवालों को संसद में उठाए. अब सवाल यह है कि क्या जमात-ए-इस्लामी की वेलफेयर पार्टी मुसलमानों की इस ज़रूरत को पूरा कर पाएगी.

प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली में राजनीतिक दलों की सबसे अहम भूमिका होती है. देश भर में क़रीब 1200 राजनीतिक दल हैं. इनमें 6 राष्ट्रीय, 44 राज्यस्तरीय और 1152 क्षेत्रीय पार्टियां हैं. हाल में बाबा रामदेव ने भी पार्टी बनाने की घोषणा की है. भारत की राजनीति में एक और पार्टी ने जन्म लिया है. यह पार्टी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद की पार्टी है. जमात ने इस पार्टी का नाम वेलफ़ेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया रखा है. जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक दल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या यह पार्टी सिर्फ़ मुसलमानों की पार्टी है, क्या यह पार्टी सिर्फ़ मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करेगी, क्या यह चुनाव लड़ेगी, किन-किन पार्टियों से यह गठबंधन कर सकती है, इस पार्टी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नज़रिया क्या है, इस पार्टी से किन पार्टियों को फ़ायदा होगा और किन पार्टियों को नुक़सान पहुंचेगा आदि जैसे कई सवाल हैं, जिनके बारे में देश की जनता और ख़ासकर मुसलमानों को जानना ज़रूरी है.

जमात-ए-इस्लामी की स्थापना 26 अगस्त, 1941 को लाहौर में हुई थी. देश के बंटवारे के बाद जमात-ए-इस्लामी भी बंट गई. पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी जमात-ए-इस्लामी है. राजनीति में हिस्सा भी लेती है. भारत में जमात पर सरकार ने दो बार प्रतिबंध भी लगाया है. पहली बार इमरजेंसी के दौरान और दूसरी बार 1992 में. पहली बार इमरजेंसी ख़त्म होते ही प्रतिबंध हट गया और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटाया. सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त यह कहा था कि जमात-ए-इस्लामी एक राजनीतिक, सेकुलर और धार्मिक संगठन है. देश में जमात-ए-इस्लामी के लाखों समर्थक हैं, इसके दस लाख से ज़्यादा सदस्य हैं. धारणा यह है कि जमात-ए-इस्लामी के सदस्य काफ़ी अनुशासित और ईमानदार हैं. यह देश में कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है. जमात-ए-इस्लामी का महिला मोर्चा भी है, जो आंध्र प्रदेश और केरल में काफ़ी सक्रिय है. जमात-ए-इस्लामी की एक शाख़ा है ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, जो कई एनजीओ के बीच समन्वय स्थापित करता है. जमात से जुड़े एनजीओ समाज कल्याण और मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसकी छात्र विंग है, जो आंध्र प्रदेश और केरल में सक्रिय है. जमात-ए-इस्लामी हिंद देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है.

नई पार्टी के ऐलान के बाद यह समझना ज़रूरी है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या यह सिर्फ़ मुसलमानों के मुद्दे उठाएगी या फिर मुसलमानों को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ेगी. जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा को समझने के लिए इसके 2006 के दस्तावेज़-विज़न 2016 को जानना ज़रूरी है. जमात ने 550 करोड़ रुपये के बजट से ग़रीब मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया था. इस प्लान के तहत 58 पिछड़े ज़िलों को चुना गया. इन ज़िलों में स्कूल, अस्पताल, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, लघु उद्योग और सस्ते घरों के लिए क़र्ज़ देने की सुविधा है. जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा बाज़ारवाद, उदारवाद और वैश्वीकरण के ख़िलाफ़ है. यह विदेशी पूंजी, सेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सेवाओं, कृषि में सब्सिडी ख़त्म किए जाने की सरकारी नीतियों का विरोध करती है. जमात का मानना है कि देश के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार का दायित्व है. जमात हर क़िस्म के आतंकवाद का भी विरोध करती है. जमात-ए-इस्लामी की विदेश नीति अमेरिका विरोध की है. जमात-ए-इस्लामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाती है. अलग-अलग राज्यों में यह चुनाव के दौरान रणनीति बनाती है. किस पार्टी को समर्थन देना है, यह जमात सोच समझ कर फ़ैसला लेती है. इस बार के विधानसभा चुनाव में केरल में माकपा के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को जमात का खुला समर्थन मिला है. जमात अब तक के चुनावों में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को समर्थन देती रही है, जबकि इस पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में समर्थन दिए जाने के आरोप लगते रहे हैं.

जमात-ए-इस्लामी का राजनीति से रिश्ता कोई नया नहीं है. पहले यह एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती थी, अब राजनीतिक दल बन गई है. फ़र्क़ बस इतना है कि पहले चुनाव नहीं लड़ती थी, अब चुनाव लड़ेगी. तो अब सवाल यह उठता है कि जमात-ए-इस्लामी के नेताओं को चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी. इस सवाल पर जमात-ए-इस्लामी का कहना है कि आज़ाद देश में मुसलमान ख़ुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और किसी भी सियासी दल ने उनकी कभी सुध नहीं ली. इसलिए यह ज़रूरी है कि कोई ऐसी सियासी पार्टी बने, जो मुसलमानों के लिए ईमानदारी से काम करे. जमात के वरिष्ठ सदस्य एवं वेलफ़ेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष मुज्तबा फ़ारूक का कहना है कि मुसलमानों की बदतर हालत को देखते हुए जमात को पहले ही अपनी सियासी पार्टी बना लेनी चाहिए थी. नई पार्टी का मक़सद मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है. वह कहते हैं कि हम पार्टियों की क़तार में जुड़ने के लिए सियासत में नहीं आ रहे हैं. हमारा मक़सद मुल्क की अवाम को एक नया विकल्प मुहैया कराने का है. यह पार्टी सबकी है. हम सभी की आवाज़ बनना चाहते हैं.

वेलफ़ेयर पार्टी की कार्यकारिणी में फ़िलहाल 31 सदस्य होंगे. इलियास आज़मी, फ़ादर अब्राहम जोसेफ़, मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी, मौलाना जफ़रुल इस्लाम ख़ान और ललिता नायर को उपाध्यक्ष बनाया गया है. एसक्यूआर इलियास, सुहैल अहमद, प्रो. रमा पांचल, ख़ालिदा परवीन और पीसी हम्ज़ा को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावा प्रो. रमा सूर्य राव, अख्तर हुसैन अख्तर, ओमर रशीद और प्रो. सुब्रमण्यम पार्टी के सचिव होंगे. अब्दुस सलाम इस्लाही को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन कर सकती है. भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक सांप्रदायिक पार्टी है. कश्मीर के अलगाववादी दलों के बारे में भी उनका यही जवाब रहा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए. जम्मू और कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की तरफ़ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को इतना मजबूर भी नहीं किया जाना चाहिए कि वह हथियार उठा ले. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं और महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारेगी तथा ग़ैर मुसलमानों को भी पार्टी के टिकट दिए जाएंगे. उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों को एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए, सही मायनों में वे अभी तक नहीं मिल पाए हैं. मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है. उन्हें नहीं पता कि कब हालात बदलें और उनकी जान व माल को ख़तरा पैदा हो जाए. देश की मौजूदा व्यवस्था का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसने अमीर को और अमीर तथा ग़रीब को और ज्यादा ग़रीब बनाने का ही काम किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करेगी. मुसलमानों को आरक्षण दिलाने, इस्लामिक बैंक प्रणाली की स्थापना, सच्चर समिति की सिफ़ारिशों को लागू कराने आदि पर भी ज़ोर दिया जाएगा. इसके अलावा महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे.

वेलफ़ेयर पार्टी की कार्यकारिणी में फ़िलहाल 31 सदस्य होंगे. इलियास आज़मी, फ़ादर अब्राहम जोसेफ़, मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी, मौलाना जफ़रुल इस्लाम ख़ान और ललिता नायर को उपाध्यक्ष बनाया गया है. एसक्यूआर इलियास, सुहैल अहमद, प्रो. रमा पांचल, ख़ालिदा परवीन और पीसी हम्ज़ा को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावा प्रो. रमा सूर्य राव, अख्तर हुसैन अख्तर, ओमर रशीद और प्रो. सुब्रमण्यम पार्टी के सचिव होंगे.

जमात-ए-इस्लामी की वेलफेयर पार्टी के निशाने पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है. फ़िलहाल इस पार्टी का दख़ल दक्षिण के राज्यों और उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा. अगर जमात-ए-इस्लामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी ताक़त लगा दे और अगर इसे मुसलमानों का समर्थन मिला तो देश की राजनीति में सुनामी आ सकती है, जिसका असर हर छोटे-बड़े राजनीतिक दल पर पड़ेगा. इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और सबसे बड़ा नुक़सान समाजवादी पार्टी को होगा. यही वजह है कि पार्टी की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी से तीखी प्रतिक्रिया मिली. समाजवादी पार्टी के महासचिव एवं प्रवक्ता सांसद मोहन सिंह ने कहा कि यह सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है और कुछ नहीं. जनता बेवकूफ़ नहीं है. लोग सब समझते हैं. अगर वेलफ़ेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया चुनाव लड़ती है तो जनता इसके उम्मीदवारों को ख़ारिज कर देगी. उनका यह भी कहना है कि मज़हबी संगठनों का सियासत में कोई काम नहीं है. इसलिए बेहतर है कि वे अपने धार्मिक कार्यों पर ही ध्यान दें. ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर मुसलमान समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं. ऐसे में नई पार्टी के आ जाने से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है. नुक़सान सिर्फ़ समाजवादी पार्टी का ही नहीं होगा. राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को फिर से मज़बूत करने में लगे हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था. इसकी वजह यह थी कि पूर्वांचल के मुस्लिम बहुल इलाक़ों में कांग्रेस को मुसलमानों का भारी समर्थन मिला. समझने वाली बात यह है कि जमात की ताक़त भी इन्हीं इलाक़ों में हैं. दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग के सुझावों को लागू करने में अब तक नाकाम रही है, जिससे उसका मुस्लिम समर्थन घटना तय है. फ़तेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुक़र्रम का कहना है कि अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए मुसलमानों का सियासत में आना बेहद ज़रूरी है. इसके लिए लाज़िमी है कि मुसलमानों का अपना एक सियासी दल हो. ऐसा दल, जो ईमानदारी के साथ क़ौम की तरक़्क़ी के लिए काम करे. जब तक मुसलमानों की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक उनकी हालत बेहतर होने वाली नहीं है. उनका यह भी कहना है कि ख़ुद को सेकुलर कहने वाले कांग्रेस जैसे सियासी दलों ने मुसलमानों के लिए कोई संतोषजनक काम नहीं किया है. मुसलमानों की स्थिति दलितों से ज़्यादा अच्छी नहीं है. देश में दलितों के कई राजनीतिक दल हैं. ऐसे में मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए एक राजनीतिक दल की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन इस पार्टी के चुनाव में उतरते ही इसे सेकुलर पार्टियों का विरोध झेलना पड़ जाएगा. कल तक जो नेता जमात-ए-इस्लामी के साथ चुनावी फ़ायदे के लिए अच्छा रिश्ता रखते थे, वही इस पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे. इस पार्टी को मुस्लिम नेताओं का विरोध झेलना पड़ेगा. ख़ासकर उन मुस्लिम नेताओं का, जो मुस्लिम वोटों का सपना दिखाकर पार्टी में मज़बूत ओहदे पर पहुंचे हैं. इस पार्टी पर आरोप भी लगेंगे. मुस्लिम नेता ही कहेंगे कि जमात ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया तो उसकी पार्टी कौन सा क़ौम को निहाल कर देगी. इस पार्टी पर यह भी आरोप लगेगा कि जमात ने चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है. इन सब सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा. मुश्किल इसलिए, क्योंकि यह पार्टी जितनी मज़बूत होगी, भारतीय जनता पार्टी को उतना ही फ़ायदा होगा.

वेलफेयर पार्टी की शुरुआत अच्छी है. विचारधारा के नाम पर अमेरिका, वैश्वीकरण, उदारवाद और बाज़ारवाद का विरोध इसे जनता से जोड़ेगा. जमात के पास मज़बूत संगठन है. इसका भी फ़ायदा मिलेगा. कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होगी, लेकिन इस पार्टी को अभी कई मुश्किलों का सामना करना है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है. पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के बड़े-बड़े लोगों को अपने बैनर में शामिल तो किया है, लेकिन राजनीति की विशेषता है कि बिना लीडरशिप के पार्टी बिखरने लगती है. पार्टी का नेता बनने की प्रतिस्पर्धा में नेता आपस में लड़ने लगते हैं. ऐसे में पार्टी का अस्तित्व दांव पर लग जाता है. वेलफेयर पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट है. किसी भी मुस्लिम पार्टी के लिए यह ज़रूरी है कि उसके पास ऐसा नेता हो, जो न सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय का नेता हो, बल्कि उसे देश के दूसरे समुदाय के लोग भी अपना नेता मानें. अब ऐसा नेता कहां से आएगा, यही

firdaus@chauthiduniya.com

तृणमूल को शर्मसार करने की एक करतूत मुकुल राय के बेटे शुभ्रांग्शु राय ने की, जिसने चुनाव आयोग के अफसरों को पीट दिया.

पश्चिम बंगाल
बदलाव की बयार और वाममोर्चा

बिमल राय

राज्य विधानसभा चुनाव के इस आख़िरी दौर में नए-नए मुद्दों के ज़रिए राजनीतिक पैतरेबाज़ी के नित नए-नए रूप देखने को मिल रहे हैं. काला धन और भ्रष्टाचार का मुद्दा तो पूरे देश में दौड़ रहा है, पर बंगाल में आवासन मंत्री गौतम देव ने तृणमूल पर काला धन जुटाने का आरोप लगाकर चुनाव प्रचार को एक नई रंगत दे दी है. यह इसलिए भी ध्यान खींच रहा है कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है. देश में काले धन का पता लगाने में भले ही केंद्र सरकार को पसीने छूट रहे हों, पर माकपा ने इस कथित काले धन का पता अपने हंसिया-हथौड़ा धारकों के ज़रिए लगाया है. आवासन मंत्री की बातों पर यक़ीन करें तो बीते 25 मार्च को कोलकाता के तृणमूल भवन में केंद्रीय मंत्री मुकुल राय ने पार्टी के सभी 226 प्रत्याशियों को 15-15 लाख रुपये दिए. इस राशि के साथ-साथ प्रत्याशियों को चंदा उगाही के कूपन भी दिए जा रहे थे, जिन्हें बक्सों से निकालने का काम माकपा समर्थक मज़दूर कर रहे थे. मंत्री ने बताया कि एक प्रत्याशी ने यह राशि लेने से इंकार कर दिया. अगर यक़ीन न हो तो उपेन विश्वास से पूछ लीजिए. उन्होंने पत्रकारों को उनका मोबाइल नंबर भी दे दिया. ज़ाहिर है, फोन बजने के कारण उपेन परेशान हो गए और उन्होंने इसे माकपा की एक चाल बताया. पूर्व सीबीआई अधिकारी ने 15 लाख रुपये की राशि लेने से इंकार करने वाली बात को भी ग़लत बताया. गौतम ने अपने आरोप के समर्थन में फिक्की के महासचिव एवं तृणमूल प्रत्याशी अमित मित्रा के बैंक खाते के बारे में बताया, जो 26 मार्च को खोला गया और उसमें सात लाख रुपये जमा किए गए. मंत्री ने पूछा कि एक ही दिन में कूपन के ज़रिए वह कैसे सात लाख रुपये जुटाने में कामयाब हो गए. इसे लेकर बवाल मचना ही था. ममता ने कहा कि पूछने पर पार्टी चुनाव आयोग को इसका जवाब देगी.

इधर चुनाव आयोग के अफसरों ने कहा है कि उनका काम निर्धारित सीमा के भीतर ख़र्च की निगरानी करना है, न कि आमदनी के स्रोत की. हालांकि माकपा ने इस संबंध में आयोग के सामने औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है और सीताराम येचुरी की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी से मिलने वाला है. वाममोर्चा के नेता यह भी कह रहे हैं कि काले धन की उगाही की योग्यता की वजह से ही अमित मित्रा को प्रत्याशी बनाया गया है. वह खड़े भी हुए हैं वित्त मंत्री असीम दास गुप्त के ख़िलाफ़ और ज़्यादा संभावना है कि ममता के सत्ता में आने पर उन्हें वित्त मंत्री ही बनाया जाएगा. ममता के हेलीकॉप्टर दौरों को लेकर भी माकपा के नेता टोंट मार रहे हैं और उन्हें उड़ंत पाखी (उड़ती हुई चिड़िया) कह रहे हैं. वोटरों को यह बताया जा रहा है कि हवाई चप्पल और सफेद सूती साड़ी पहनने वाली ममता के पास हर रोज किराए के लाखों रुपये कहां से आ रहे हैं. उनके मुताबिक़, अपनी चित्रकारी बेचकर ममता ने जो कुछ लाख रुपये कमाए हैं, वे एक दिन के हेलीकॉप्टर किराए के लिए भी कम हैं. ममता सवाल कर रही हैं कि वह पहले भी उड़नखटोलों का उपयोग करती रही हैं तो इस बार क्यों इतनी चिल्ल-पों मचाई जा रही है? इसकी वजह जानना भी बहुत मुश्किल नहीं है. बदलाव की तेज हवा को रोकने के लिए वाममोर्चा छोटे से छोटे मुद्दे को भी तूल देने में जुटा है. माकपा के नेता चुनावी सभाओं में यूपीए सरकार के घोटालों को उठा रहे हैं और ऐसे आरोपों के फंदे में ममता को फांसना उन्हें चुनावी फ़ायदे का काम लग रहा है. हालांकि ममता भी इस हकीक़त को समझ रही हैं और गठबंधन के बावजूद वह जनसभाओं में कांग्रेस का नाम लेने और कांग्रेसी नेताओं के साथ मंच पर दिखने से बच रही हैं. मिसाल के तौर पर उत्तर 24 परगना के हाड़ोआ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानस भुइयां के भाषण देकर चले जाने के बाद ही वह मंच पर आईं.

बताने की ज़रूरत नहीं कि बदलाव की हवा दिखने के बाद वाममोर्चा की एकमात्र उम्मीद कांग्रेस और तृणमूल के बीच दूरी थी. हालांकि इन दोनों के बीच गठबंधन हुआ है, पर यह बेमन का ही ब्याह लगता है. कोलकाता की पोर्ट सीट पर राम प्यारे राम और बगल की सीट पर एक दूसरे कांग्रेसी नेता बग़ावत कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, पर इससे गठबंधन के बदले वाममोर्चा को फ़ायदा होने की उम्मीद है. राम प्यारे जीत के प्रति आश्वस्त हैं, पर दूसरी सीट वाममोर्चा के खाते में जा सकती है. मुर्शिदाबाद के राबिनहुड अधीर रंजन चौधरी पर हाथ डालने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं है. बीते 19 अप्रैल को जब केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की रैलियां कर रहे थे तो मंच पर अधीर नहीं थे और वह हरिहरपाड़ा, सागरदिघी, जालंगी और भगवानगोला सीटों पर तृणमूल उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ खड़े किए गए निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रचार में लगे थे. इलाक़े में हुई जनसभाओं में ममता ने मीरजाफर की चर्चा करके इशारों में अधीर पर निशाना साधा. इससे राबिनहुड और गुस्सा गया है. ममता को फूटी आंख न सुहाने वाली दीपा दासमुंशी ने उत्तर दिनाजपुर ज़िले में बग़ावत का मोर्चा संभाला है. इस्लामपुर, हेमताबाद और चोपड़ा में वह निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ हैं. पार्टी के विरोध के बावजूद गनी ख़ान के भाई ए एच ख़ान चौधरी ने वैष्णव नगर सीट से अपने बेटे इशा ख़ान को टिकट दिलवाया है, जबकि मोथाबाड़ी सीट पर उन्होंने पार्टी की असली प्रत्याशी सबीना यास्मीन के मुक़ाबले निर्दलीय शहनाज कादरी का समर्थन किया है. इस तरह दीपा दासमुंशी, अधीर और गनी खान परिवार के गढ़ में वोटों के बंटवारे से भी वाममोर्चा को फ़ायदा हो सकता है.

ममता सवाल कर रही हैं कि वह पहले भी उड़नखटोलों का उपयोग करती रही हैं तो इस बार क्यों इतनी चिल्ल-पों मचाई जा रही है? इसकी वजह जानना भी बहुत मुश्किल नहीं है. बदलाव की तेज हवा को रोकने के लिए वाममोर्चा छोटे से छोटे मुद्दे को भी तूल देने में जुटा है. माकपा के नेता चुनावी सभाओं में यूपीए सरकार के घोटालों को उठा रहे हैं और ऐसे आरोपों के फंदे में ममता को फांसना उन्हें चुनावी फ़ायदे का काम लग रहा है.

तृणमूल को शर्मसार करने की एक करतूत मुकुल राय के बेटे शुभ्रांग्शु राय ने की, जिसने चुनाव आयोग के अफसरों को पीट दिया. केस दर्ज होने के बाद यह सपूत फरार हो गया और पकड़ा भी गया तो ममता के चुनावी मंच से उतरते हुए. माकपा के नेता इस मुद्दे को भी उछाल रहे हैं कि ममता एक आरोपी को बचा रही हैं और पार्टी क़ानून की इज़्ज़त करना नहीं जानती. वैसे भी माकपा कहती रही है कि ममता के सत्ता में आने पर राज्य में अराजकता पैदा होगी. पश्चिम मिदनापुर में पुलिस अत्याचार के ख़िलाफ़ बनी जनसाधारणेर कमेटी के मुखिया छत्रधर महतो जेल में रहकर ही चुनाव लड़ रहे हैं. इस वजह से नक्सल प्रभावित कुछ सीटों पर वाम विरोधी मतों का बंटवारा हो सकता है और बदलाव की हवा को झटका लग सकता है. शुक्र है कि कमेटी केवल एक सीट से चुनाव लड़ रही है, नहीं तो जंगल महल का पूरा चुनावी समीकरण बदल जाता. ऐसा नहीं है कि वाममोर्चा दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ पा रहा है, पर उसकी कोशिश बदलाव की हवा को सुनामी बनने से रोकने की है. राज्य में शुरुआती चरणों के मतदान का अधिक प्रतिशत इस सुनामी की ओर ही संकेत कर रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर रेलवे कारख़ाना
बंदी की कगार पर

अफ़ज़ल इमाम मुन्ना

वर्ष 1881 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित समस्तीपुर रेलवे कारखाना सरकारी उदासीनता के चलते बंदी की कगार पर पहुंच गया है. यह उत्तर बिहार का इकलौता रेलवे कारखाना है. यहां 1907 में हुई हड़ताल ट्रेड यूनियन आंदोलन की अमूल्य धरोहर है. इस कारखाने के अधिकांश कार्य गोरखपुर और इज्जत नगर स्थित कारखानों को सौंप दिए गए हैं. अब तो यहां बड़ी लाइन के डिब्बों और इंजनों की मरम्मत का कार्य भी नहीं कराया जाता, जबकि पहले एमजी के इंजनों एवं वैगनों की मरम्मत (पीओएच) हुआ करती थी. वर्तमान में केवल बड़ी लाइन के बाक्सन-एचएल वैगनों का निर्माण होता है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स के अभाव में यह काम भी पिछले आठ महीनों से बंद है. अगस्त 2010 में 25 बाक्सन-एचएल वैगनों का निर्माण हुआ था, लेकिन स्पेयर पार्ट्स (कप्लर) के अभाव के चलते सितंबर 2010 से अब तक एक भी वैगन का निर्माण नहीं हुआ. कर्मचारियों के चेहरे पर उदासी है. उन्हें लगता है कि शायद इस कारखाने को बंद करने की साजिश की जा रही है.

कारखाने के कर्मचारियों ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की कारखाना स्टोर शाखा के सचिव वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कई बार धरना-प्रदर्शन आदि भी किए, अब मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय का घेराव करने की तैयारी चल रही है. कारखाने की उपेक्षा के चलते आम लोगों में भी काफी नाराज़गी है, लेकिन समस्तीपुर के सांसद महेश्वर हजारी को फुर्सत नहीं है कि वह इस ओर ध्यान दें. मालूम हो कि इसी रेलवे कारखाने की उपेक्षा के कारण वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में झोपड़ी के लाल के रूप में मशहूर महान समाजवादी नेता एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और क्षेत्र की उपेक्षा के कारण पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में नीतीश लहर के बावजूद रामनाथ ठाकुर को पराजय का मुंह देखना पड़ा था.

इस रेलवे कारखाने की उपेक्षा वर्षों से हो रही है, लेकिन ट्रेड यूनियन और आम नागरिकों के विरोध के कारण यह अभी तक जिंदा है. इस कारखाने में पहले एमजी के रेल इंजनों और वैगनों की मरम्मत का कार्य होता था, जिसके लिए 1800 से ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त थे, लेकिन अचानक मरम्मत का कार्य इस कारखाने में बंद कर दिया गया. इंजन मरम्मत का कार्य पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कारखाने और कैरेज मरम्मत का कार्य इज्जत नगर कारखाने में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि समस्तीपुर कारखाने के मज़दूरों की कार्य कुशलता उच्च कोटि की थी और उनके द्वारा उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता था. इसका उदाहरण 1976 और बाद के वर्षों में प्रतिरक्षा विभाग के लिए 114 एमवीडब्ल्यूजेड वैगनों का सफलतापूर्वक निर्माण निर्धारित समय से पहले पूरा करना है, जिसके लिए भारत सरकार ने इस कारखाने को पुरस्कृत भी किया था. कारखाने में पहले 3500 कर्मचारी कार्यरत थे, अब मात्र 557 कर्मचारी शेष रह गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल के 88 कर्मचारी भी शामिल हैं. इस प्रकार 2943 कर्मचारियों को सेवा से वंचित कर दिया गया.

कारखाने में 1983 से कैरेज मरम्मत का कार्य बंद कर दिया गया. इसके बाद यात्री डिब्बों के पीओएच (वैगन मरम्मत), कैरेज एवं वैगनों के रखरखाव के काम आने वाले स्पेयर पार्ट्स के निर्माण का काम बंद हो गया. फिर मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण होने लगा, बाद में इसे भी बंद कर दिया गया. 1990 में जब वैगन मरम्मत का काम बंद कर दिया गया तो समस्तीपुर विस्तार विकास मंच, ट्रेड यूनियनों और आम नागरिकों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया. परिणामस्वरूप 1992 से यहां बड़ी रेल लाइन के बाक्सन वैगन का निर्माण कार्य शुरू हुआ. यह कार्य तब शुरू हुआ, जब सीतामढ़ी के तत्कालीन सांसद नवल किशोर राय ने तत्कालीन रेल मंत्री सी के जाफर शरीफ से मिलकर उन्हें इस कारखाने की स्थिति से अवगत कराया. जाफर शरीफ ने कारखाने के भविष्य को देखते हुए बड़ी रेल लाइन की माल गाड़ियों के लिए बाक्सन वैगन निर्माण का कार्य शुरू करने का आदेश दिया. वर्ष 1989 में केंद्र की कांग्रेस सरकार चली गई और वी पी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी. तब रेल मंत्री जार्ज फर्नांडीज ने इस कारखाने को 60 बाक्सन-एचएल वैगन प्रति वर्ष तैयार करने का आदेश दिया था. वर्तमान में यह कारखाना 300 वैगन प्रति वर्ष तैयार कर रहा है. सितंबर 1992 से लेकर अप्रैल 2010 तक इस कारखाने में 3494 बाक्सन-एचएल वैगनों का निर्माण हो चुका है. अभी भी 300 वैगनों का ऑर्डर पूरा होना शेष है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स (कप्लर) के अभाव में काम बंद है. बताते हैं कि विभागीय लापरवाही के कारण समय पर टेंडर पास नहीं हुआ. नतीजतन न्यूयार्क से आने वाले उक्त स्पेयर पार्ट्स भारतीय रेल के किसी भी कारखाने को मुहैया नहीं हो रहे. जबकि यही पार्ट्स निजी कारखानों को आसानी से उपलब्ध हैं. फलस्वरूप वैगन तैयार करके वे मालामाल हो रहे हैं.

22 दिसंबर, 2005 को तत्कालीन रेल मंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी इस कारखाने का निरीक्षण किया था और समस्तीपुर डीजल शेड के विस्तार की घोषणा की थी. उन्होंने रेल बजट में इसके लिए धन की व्यवस्था की और 9 अक्टूबर, 2007 को डीजल शेड में दोनों योजनाओं का शिलान्यास भी किया था. 49.12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सी कैटेगरी रेल कारखाने का निर्माण अभी जारी है. कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय सी कैटेगरी रेल कारखाने को निजी हाथों में सौंपने जा रहा है. यही कारण है कि मालगाड़ी के डिब्बों की मरम्मत का काम शुरू करने के लिए 736 कर्मचारियों की नियुक्ति की जो मंजूरी मांगी गई थी, वह फाइल पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर स्थित मुख्यालय में महाप्रबंधक (कार्मिक) के यहां धूल खा रही है. इस बीच इस काम को आउटसोर्सिंग से कराने की बात चल रही है, जिससे मज़दूरों में आक्रोश है. बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार भी इस कारखाने का निरीक्षण और कर्मचारियों को ईनाम के तौर पर पांच लाख रुपये देकर कारखाने के विस्तार की दिशा में पहल कर चुके हैं. राजद विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने इस कारखाने में कर्मचारियों की कमी, कार्यों में कटौती और सी कैटेगरी कारखाने को निजी हाथों में देने की बात पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि समस्तीपुर रेलवे कारखाने में बड़ी रेल लाइन के कैरेज मरम्मत का काम फिर से शुरू हो, स्पेयर पार्ट्स जल्द मुहैया हो और सी कैटेगरी कारखाने को निजी हाथों में न सौंपा जाए. कारखाने के लिए 736 कर्मचारियों की स्वीकृति जल्द से जल्द दी जाए, ताकि स्थानीय बेरोज़गारों को इसका लाभ मिल सके.

feedback@chauthiduniya.com